and Billet Mills during March 1967; and

(iv) *Difficult labour situation during June 1967.*

(d) Action to remove transport bottlenecks is already in hand. Strenuous efforts are also being made to step up exports of various steel items

Chaparmukh-Silghat Section of North-East Frontier Railway

6461. Shri Bedabrata Barua: Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the lease granted to M/s Martin Burn & Company in regard to the running of the Chaparmukh-Silghat Section of the North-East Frontier Railway expires in 1968;

(b) whether this arrangement of granting leases has been very unsatisfactory to Government, company and the public; and

(c) whether Government propose to run this section after 1968?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) No, there is no such lease.

(b) Does not arise in view of answer to (a) above.

(c) Although this line is owned by the Chaparmukh-Silghat Railway Company Ltd. for whom Martin Burn and Co are the Managing Agents, the Chaparmukh-Silghat Section is being worked since its inception by the Government as a part of the North-east Frontier Railway under an agreement dated the 14th November 1918 between the Chaparmukh-Silghat Railway Co. and the then Secretary of State for India. Government will continue working the line after 1968 also.

चाय का निर्यात

6462. श्री बरुआ : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक सरकारी विशेषज्ञ समिति ने चौथी पंचवर्षीय योजना के 30 करोड़ किलोग्राम चाय का निर्यात करने के निर्धारित लक्ष्य में 20 प्रतिशत कटौती करने की सिफारिश सरकार से की है;

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि उस समिति ने चौथी पंचवर्षीय योजना में चाय के उत्पादन के लिये निर्धारित 45 करोड़ 40 लाख किलोग्राम के लक्ष्य को कम करके 42 करोड़ किलोग्राम कर देने का सुझाव दिया है; और

(घ) यदि हां, तो समिति ने ऐसा करने के क्या कारण बताये हैं तथा उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ।

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) तथा (ग). जी हां ।

(ख) तथा (घ). समिति ने चाय के उत्पादन तथा निर्यात के लिए जो संशोधित लक्ष्य सुझाये हैं वे उसके अपने अनुमान के अनुसार वर्तमान प्रवृत्तियों और भविष्य की सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए 1970 तक प्राप्त किये जा सकते हैं । सरकार के विचार में चौथी योजना के मसौदे में मूलतः अपनाये गये आंकड़ों की अपेक्षा संशोधित लक्ष्य अधिक यथार्थपरक हैं और उन्हें स्वीकार करने के लिए वह तैयार है ।